RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 12 | अंक-61 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

सितंबर जीएसटी संग्रह 9.1% चढ़ा, मंदी की आशंकाओं को झुठलाया

कर दरों में छूट और त्योहारी मांग ने बढ़ाया राजस्व, नेट कलेक्शन 5% ऊपर

नई दिल्ली: भारत की अर्थव्यवस्था को राहत देते हुए सितंबर 2025 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 9.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.89 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यह वृद्धि आर्थिक मंदी की अपेक्षाओं के विपरीत है, जहां विशेषज्ञों ने कमजोर मांग और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच संग्रह में गिरावट का अनुमान लगाया था। पिछले महीने अगस्त में यह 1.86 लाख करोड़ रुपये था, जबकि सितंबर 2024 में 1.73 लाख करोड़ रुपये रहा था।

इस उछाल का प्रमुख कारण 22 सितंबर से लागू जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत 375 वस्तुओं पर कर दरों में कटौती है, जिससे रसोई सामग्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाओं और ऑटोमोबाइल्स तक की कीमतें घटीं। इससे उपभोक्ता मांग में तेजी आई, खासकर त्योहारी सीजन की शुरुआत में। सकल घरेलू राजस्व 6.8 प्रतिशत बढ़कर 1.36 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयात पर कर 15.6 प्रतिशत चढ़कर 52,492 करोड़ रुपये पहुंचा। हालांकि, रिफंड दावों में 40.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 28,657 करोड़ रुपये रही। नेट जीएसटी राजस्व 5 प्रतिशत ऊपर 1.60 लाख करोड़ रुपये रहा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे "आर्थिक लचीलापन" का प्रमाण बताया, जबकि अर्थशास्त्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा, "यह सुधारों का सकारात्मक परिणाम है, जो व्यवसायों को बढ़ावा देगा।" फिर भी, कुछ विशेषज्ञ सतर्क हैं, क्योंकि पिछले दो महीनों में वृद्धि एकल अंकीय रही है। राज्यों में महाराष्ट्र (18,000 करोड़ रुपये से अधिक) और कर्नाटक शीर्ष पर रहे।

यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम है, जो विकास परियोजनाओं को गति देगा। लेकिन वैश्विक व्यापार युद्ध और मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियां बनी रहेंगी। निवेशक अब अक्टूबर के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जो त्योहारों की असली ताकत दिखाएंगे।

आरबीआई ने कहा- यूपीआई फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा: आईपीओ लोन लिमिट बढ़ाकर ₹25 लाख की, शेयर्स के बदले अब ₹1 करोड़ तक लोन मिल सकेगा

डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा, निवेशकों के लिए राहत भरा फैसला

भोपाल: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर किसी भी तरह के शुल्क लगाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद कहा, "यूपीआई लेनदेन पर कोई चार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है।" यह बयान जुलाई में गवर्नर के एक बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता पर चिंता जताई थी, जिससे बाजार में अनिश्चितता पैदा हो गई थी।

यूपीआई, जो 2016 में लॉन्च हुआ था, भारत के डिजिटल पेमेंट्स का मुख्य आधार बन चुका है। राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 में यूपीआई ने 20 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सितंबर में भी 19.63 अरब लेनदेन हुए, जो 31 प्रतिशत सालाना वृद्धि को इंगित करता है। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, "सरकार सब्सिडी के माध्यम से यूपीआई को मुफ्त रख रही है, लेकिन सिस्टम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लागत वहन का मुद्दा भविष्य में विचारणीय है। फिलहाल, यह उपयोगकर्ताओं के लिए शून्य लागत वाला प्लेटफॉर्म बना रहेगा।"

एक ओर जहां यूपीआई को राहत मिली, वहीं निवेशकों के लिए आरबीआई ने बड़ा तोहफा दिया। बैंक द्वारा शेयरों के बदले लोन की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। इसी तरह, आईपीओ फाइनेंसिंग की सीमा 10 लाख से 25 लाख रुपये हो गई। गवर्नर ने कहा, "ये सीमाएं कई वर्षों से अपरिवर्तित थीं, इसलिए इन्हें अपडेट करना स्वाभाविक था।" यह कदम प्राइमरी मार्केट में भागीदारी बढ़ाने और पूंजी बाजार में तरलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव उच्च-नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनआई) को आकर्षित करेंगे। एंबरीश बालिगा, एक स्वतंत्र मार्केट विश्लेषक ने कहा, "यह बाजार की गहराई बढ़ाएगा और आईपीओ में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।" हालांकि, बाजार में उत्साह के बावजूद, कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि बाजार सुधार के समय कोलैटरल वैल्यू में गिरावट से बैंक नुकसान झेल सकते हैं।

एमपीसी ने रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.8 प्रतिशत तथा मुद्रास्फीति 2.6 प्रतिशत किया। ये फैसले आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित हैं। डिजिटल इंडिया की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।

टाटा मोटर्स का ऐतिहासिक विभाजन: कमर्शियल वाहन इकाई अलग, शेयरों में तेजी

निवेशकों को 1:1 अनुपात में नया शेयर, मूल्य अनलॉक की उम्मीदें बढ़ीं

भोपाल: भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने आज से अपना व्यवसाय दो अलग-अलग इकाइयों में विभाजित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मंजूरी के बाद यह डिमर्जर प्रभावी हो गया है, जिसके तहत कंपनी का कमर्शियल वाहन (सीवी) व्यवसाय 'टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड' (टीएमएलसीवी) के रूप में अलग हो गया। बाकी पैसेंजर वाहन (पीवी) व्यवसाय, जिसमें जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं, 'टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड' (टीएमपीवी) के नाम से चलेगा।

इस घोषणा के बाद टाटा मोटर्स के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। निवेशकों का उत्साह इसलिए भी बढ़ा क्योंकि हर मौजूदा शेयरहोल्डर को टीएमएलसीवी का एक-एक शेयर मुफ्त मिलेगा। रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 तय की गई है, जिसके बाद 15 अक्टूबर से मूल शेयर एक्स-सीवी ट्रेडिंग करेंगे। नई सीवी इकाई का लिस्टिंग नवंबर में होने की संभावना है।

कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रसेकरन ने कहा, "यह विभाजन हमें प्रत्येक व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से बढ़ाने की स्वतंत्रता देगा। CV इकाई ट्रक, बस और लॉजिस्टिक्स पर फोकस करेगी, जबकि PV इकाई ईवी और लग्जरी सेगमेंट में तेजी लाएगी।" ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इसे "शेयरधारकों के लिए मूल्य अनलॉक" बताया, हालांकि जेएलआर की चुनौतियों पर सतर्कता बरतने की सलाह दी।

यह कदम 2024 में घोषित योजना का हिस्सा है, जो जुलाई 2025 से वैल्यूएशन के लिए लागू था। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कंपनी की बाजार हिस्सेदारी मजबूत होगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। हालांकि, साइबर अटैक और यूरोप-चीन बाजार की मंदी जैसी चुनौतियां बनी रहेंगी। निवेशक अब लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, जो ऑटो सेक्टर को नई दिशा दे सकता है।

RBI Unveils AI-Powered Digital Payments Shield Against Fraud Surge

Prototype in Works at Innovation Hub; Real-Time Alerts to Empower Banks and Users

Mumbai: In a bold move to fortify India's booming digital payments ecosystem, the Reserve Bank of India (RBI) is rolling out the Digital Payments Intelligence Platform (DPIP), an AI-driven system designed to detect and flag risky transactions before they cause harm. Announced during the latest Monetary Policy Committee meeting, the platform aims to slash fraud incidents, which skyrocketed to Rs 36,014 crore in FY25 a threefold jump from the previous year with digital payment scams alone accounting for Rs 520 crore across 13,516 cases.

RBI Deputy Governor T. Rabi Sankar revealed that the prototype is being developed at the RBI Innovation Hub, in collaboration with 5-10 major banks. "We're training an AI model on multi-source data including mule accounts, telecom records, and geolocation to issue pre-transaction alerts," Sankar explained. This real-time intelligence will enable banks and customers to pause suspicious activities, potentially curbing fraud at the network level.

The initiative addresses the vulnerabilities exposed by the explosive growth of UPI, which processed Rs 200 lakh crore in transactions last year a 137% surge. While fraud rates remain low relative to volumes, the RBI notes a fivefold spike in digital scams to Rs 1,457 crore in FY24, underscoring the need for proactive defenses. Private sector banks reported the highest number of card and internet frauds, highlighting systemic risks in a fragmented detection landscape.

Governor Sanjay Malhotra emphasized, "This platform will boost consumer confidence by enabling seamless, secure transactions." Experts hail it as a "game-changer," fostering real-time data sharing to outpace evolving threats like phishing and mule accounts. Complementing tools like MuleHunter.AI, DPIP will integrate with NPCI's efforts for holistic risk management.

As digital adoption accelerates, with UPI leading global real-time payments, the RBI's tech-forward approach signals a resilient future. Rollout timelines are tentative, but pilot testing with select banks is slated for early 2026. Stakeholders urge swift implementation to match the pace of innovation with ironclad security.

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेनयुस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES
Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES
We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:
1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in
write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

US Government Shutdown: Why It Happened and Its Impact on Indian Markets, Crypto, and Gold

The United States government shutdown is once again in the spotlight, raising concerns not only within America but also across global markets, including India. A government shutdown occurs when the US Congress fails to pass funding bills for federal operations, leading to the temporary suspension of many public services and federal employees being furloughed. This deadlock often arises due to political disagreements over budget allocations, social spending, or debt ceiling limits.

The most recent shutdown reflects deep political polarization in Washington, where disputes between Republicans and Democrats over fiscal policies have delayed the approval of government funding. While shutdowns are temporary, they create significant uncertainty in the global financial system, as the US remains the largest economy and a hub for global trade and investments.

Impact on the Indian Stock Market

Indian stock markets are closely linked with global investor sentiment. During a US shutdown, foreign institutional investors (FIIs) often turn risk-averse, pulling money out of emerging markets like India and moving it into safe-haven assets. This capital flight can lead to short-term volatility, with indices such as Nifty and Sensex witnessing downward pressure. Additionally, sectors that are heavily dependent on exports to the US, such as IT and pharmaceuticals, may face concerns over delayed government contracts and reduced consumer demand.

However, history shows that shutdowns in the US tend to have only temporary effects. For example, the 2013 shutdown lasted 16 days but had minimal long-term impact on the Indian economy. Indian markets usually stabilize once the US government resolves its budget crisis, and long-term growth prospects remain intact.

Effect on the Crypto Market

Cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum often behave differently during such crises. On one hand, uncertainty in the traditional financial system can drive investors toward decentralized assets like crypto. On the other, reduced liquidity in global markets and regulatory delays in the US during shutdowns may restrict crypto trading volumes. Historically, crypto has shown mixed responses, sometimes rallying as a hedge against instability and at other times falling due to weaker investor appetite for risky assets.

Gold as a Safe Haven

Gold has consistently been the biggest beneficiary of US government shutdowns. Investors worldwide tend to flock to gold when political and economic uncertainty rises, driving prices higher. For Indian investors, this is a double-edged sword while it strengthens the value of gold holdings, it also increases import costs, widening the current account deficit. With India being one of the largest consumers of gold, rising international prices may impact domestic demand, especially during the festive and wedding season.

Lessons from the Past

Past shutdowns teach us that while immediate volatility in stock markets, crypto, and commodities is expected, the long-term fundamentals remain unaffected. For Indian investors, the key takeaway is not to panic but to diversify across asset classes. Holding a mix of equities, gold, and digital assets can help balance risk during global uncertainties. Additionally, tracking global cues and focusing on India's domestic growth story provides more stability than reacting solely to US political drama.

In conclusion, the US government shutdown reminds investors of the interconnectedness of the world economy. While it may bring short-term ripples across Indian markets, history suggests resilience and recovery once the political deadlock is resolved.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

अशोक लीलैंड की सितंबर बिक्री में 9% की मजबूत बढ़ोतरी

एलसीवी सेगमेंट में 15% उछाल, घरेलू बाजार ने दिया बल

चेन्नई: भारत की प्रमुख कमर्शियल वाहन कंपनी अशोक लीलैंड ने सितंबर 2025 में कुल बिक्री में 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने 18,813 वाहन बेचे, जो पिछले साल के सितंबर में 17,233 यूनिट से अधिक है। घरेलू बाजार में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 17,209 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि निर्यात में उल्लेखनीय सुधार देखा गया।

मध्यम एवं भारी कमर्शियल वाहन (एमएंडएचसीवी) सेगमेंट में ट्रक और बसों की संयुक्त बिक्री 11,808 यूनिट रही, जो 7 प्रतिशत ऊपर है। हालांकि, इस सेगमेंट में ग्रोथ मॉडरेट रही, लेकिन लाइट कमर्शियल वाहन (एलसीवी) ने बाजी मारी। एलसीवी बिक्री 15 प्रतिशत चढ़कर 6,701 यूनिट हो गई, जो छोटे एवं मध्यम व्यवसायों की बढ़ती मांग को दर्शाती है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ धीरज पांडेय ने कहा, "यह वृद्धि हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो की मजबूती और ग्राहक विश्वास का प्रमाण है। त्योहारी सीजन की शुरुआत में मांग में तेजी आई है।" विशेषज्ञों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की रिकवरी ने सेक्टर को बल दिया। हालांकि, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियां बनी हुई हैं।

अगस्त 2025 की तुलना में सितंबर में 23 प्रतिशत की मासिक वृद्धि ने कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अशोक लीलैंड 1.8 लाख यूनिट का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह प्रदर्शन हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी को ऑटो सेक्टर में अग्रणी बनाए रखेगा। निवेशक अब अक्टूबर के आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं, जो त्योहारों की असर दिखाएंगे।

MUFG Eyes $2.6B Stake in Shriram Finance Amid Denials: Largest FDI in Indian NBFC?

Advanced Talks for 20% Primary Issuance Spark Buzz, But Company Labels Reports as 'Speculation'

Mumbai: Japan's Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the world's largest bank by assets, is reportedly in advanced negotiations to acquire a 20% stake in Shriram Finance Ltd., India's second-largest non-banking financial company (NBFC), for approximately $2.6 billion (₹23,200 crore), according to sources cited by the Economic Times. The potential deal, which could mark the biggest foreign direct investment in an Indian NBFC, involves a primary issuance through preferential allotment, with no secondary share sales. Both parties have allegedly signed an exclusivity agreement, and MUFG is open to increasing its holding to a controlling interest over time. However, Shriram Finance swiftly denied the reports in a stock exchange filing on September 30, labelling them "rumour and speculation." The company stated it has no knowledge of any majority stake sale discussions or shareholder intentions to divest, emphasizing transparency to curb misinformation. MUFG also declined to comment, fuelling uncertainty.

Shriram Finance, with assets under management (AUM) of ₹2.72 lakh crore and nearly 10 million customers in vehicle finance, MSME loans, and gold loans, reported an 8.8% year-on-year profit rise to ₹21.56 billion in the June quarter. Its shares surged 3.5% to ₹617 on September 30 amid the buzz, reflecting market optimism despite the denial.

This comes as Japanese banks ramp up India investments amid domestic stagnation. Rival Sumitomo Mitsui recently took a 20% stake in Yes Bank for $1.58 billion. Analysts see the

vmove as strategic for MUFG to tap India's $500 billion lending market, but regulatory approvals and valuation at current price levels remain hurdles. Shriram, with promoters holding 25.39% and foreign investors at 52.61%, could benefit from global expertise if talks materialize. Investors await clarity, as the saga underscores NBFC sector's allure for overseas capital.

Reliance Brands Teams Up with Stella McCartney to Pioneer Ethical Luxury in India

Vegan Fashion Icon Enters Booming Market via Multichannel Rollout, Targeting Eco-Conscious Consumers

Mumbai: In a move blending global sustainability with India's retail prowess, Reliance Brands Limited (RBL), a subsidiary of Reliance Retail Ventures, has forged a strategic partnership with British ethical fashion pioneer Stella McCartney to launch her eponymous label across the country. Announced on October 1, the collaboration aims to introduce McCartney's cruelty-free collections featuring ready-to-wear apparel, handcrafted vegan footwear, and accessories to a burgeoning base of environmentally aware Indian shoppers.

Founded in 2001 by the lifelong vegetarian designer daughter of Beatles legend Paul McCartney Stella McCartney has long championed a "conscious luxury" ethos, eschewing leather, fur, feathers, and exotic skins in favor of innovative, planet-friendly materials. With 47 global stores in fashion hubs like London, Paris, and Tokyo, plus distribution in over 70 countries, the brand counts celebrities like Taylor Swift and Meghan Markle among its devotees. Now, RBL's multichannel approach spanning standalone boutiques, department stores, and e-commerce via Ajio Luxe will bring this vision to India, with physical stores slated to open in six months and online sales kicking off soon.

"Stella McCartney is more than a fashion brand she is a pioneer of a conscious luxury movement that challenges conventions," an RBL spokesperson enthused, highlighting India's ideal landscape for her mission amid rising eco-sentiments. A Stella McCartney representative echoed: "We're thrilled to connect with changemakers building a kinder fashion industry for Mother Earth and its creatures."This tie-up aligns with India's luxury market projections of $85-90 billion by 2030, fuelled by ultra-high-net-worth individuals, e-commerce growth, and demand from Tier-2/3 cities, per Bain & Co. RBL, already partnering with heavyweights like Burberry and Valentino across 1,500+ stores, sees this as a step to nurture premium ethical labels. Fashion experts hail it as a catalyst for sustainable practices in a sector often criticized for environmental tolls, potentially inspiring local designers. As India embraces "green glamour," this alliance could redefine luxury one vegan stitch at a time.

Nuvama Wealth Secures SEBI Greenlight to Launch Mutual Fund Arm

Sponsor Approval Paves Way for Specialized Investment Funds Amid Booming ₹68 Lakh Crore AUM Market

New Delhi: In a significant boost to India's burgeoning asset management sector, Nuvama Wealth Management Ltd has received approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to act as a sponsor for its proposed Nuvama Mutual Fund. The regulator's nod, conveyed via a letter dated October 1, 2025, allows the financial services powerhouse to establish the fund house and roll out a suite of investment schemes, including those under the innovative Specialized Investment Funds (SIF) category.

This milestone follows Nuvama's application in January 2025, marking a strategic expansion for the firm, formerly Edelweiss Wealth Management. With a robust client base exceeding 1.3 million high-net-worth individuals and assets under advisory surpassing ₹3 lakh crore, Nuvamais well-positioned to capture a slice of the mutual fund industry's explosive growth.

The sector's average assets under management (AUM) hit ₹68 lakh crore in August 2025, up 35% year-on-year, driven by retail investor influx and new product launches.

The approval enables Nuvama to launch traditional equity, debt, and hybrid schemes alongside SIFs a SEBI-introduced category in February 2025 bridging mutual funds and portfolio management services. SIFs, with a ₹10 lakh minimum investment threshold, offer sophisticated strategies like long-short equity and tax efficiency, attracting HNIs amid market volatility. Final registration, however, hinges on fulfilling SEBI's stipulated conditions, including net worth and compliance benchmarks under the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

Nuvama's entry intensifies competition, joining players like SBI and Edelweiss in the SIF race. Analysts predict it could add ₹5,000-10,000 crore to Nuvama's AUM within two years, leveraging its wealth advisory synergies. Shares surged 3.02% to ₹6,492.95 on BSE, reflecting investor optimism.

As India's mutual fund penetration rises reaching 8% of GDP this development underscores SEBI's push for innovation while safeguarding investor interests. For Nuvama, it's a gateway to diversified revenue streams, potentially transforming it into a full-spectrum wealth giant in a market eyeing ₹1 lakh crore AUM by 2030.

ICICI Prudential Unveils Conglomerate Fund: Betting on India's Business Empires

Thematic Equity NFO Opened October 3, Targets 71 Groups with Sunrise Sector Exposure

Mumbai: In a strategic play to harness the resilience of India's powerhouse business groups, ICICI Prudential Mutual Fund has launched the ICICI Prudential Conglomerate Fund, an open-ended equity scheme themed around conglomerates. The New Fund Offer (NFO) opened for subscription on October 3 and closes on October 17, with a minimum investment of ₹1,000, offering retail investors a front-row seat to the growth of diversified empires like Reliance and Adani.

This thematic fund taps into 71 promoter-led conglomerates, encompassing nearly 240 listed companies across large-, mid-, and small-cap segments. It focuses on groups with at least two listed entities spanning multiple sectors, from traditional bastions like infrastructure

business groups have reinvented themselves across decades, consolidating market share during crises while smaller players falter," said Sankaran Naren, Executive Director and CIO at ICICI Prudential AMC. The fund's portfolio will prioritize robust balance sheets and low capital costs that fuel expansions into "sunrise sectors," aiming for long-term capital appreciation.

The fund, benchmarked against the Nifty India Domestic Conglomerate Index (TRI), will maintain 80-100% equity allocation, with up to 20% in debt or money market instruments for liquidity. Both regular and direct plans, including growth and IDCW options, will be available post-NFO.

ICICI Prudential, managing over ₹7.5 lakh crore in AUM, positions this as a timely bet in volatile markets, where conglomerates' diversification shields against sector-specific downturns. Experts caution that thematic funds carry higher risks, suited for investors with a 5–7-year horizon and moderate-to-high risk appetite. "In uncertain times, conglomerates protect capital while capturing wealth creation," the fund house noted.

As India's mutual fund industry eyes ₹1 lakh crore AUM by 2030, this launch intensifies competition in thematic spaces. Early subscriptions could capitalize on lower NAVs, but thorough scheme document review is advised. With India's economy projected at 7% GDP growth, the Conglomerate Fund could redefine portfolio strategies for savvy investors.

Vedanta Pushes Demerger Deadline to March 2026 Amid Approval Delays

NCLT and Government Clearances Pending; Scheme to Create Standalone Entities for Value Unlock

New Delhi: Vedanta Ltd, the Anil Agarwal-led mining conglomerate, has extended the deadline for its much-anticipated demerger to March 31, 2026, from September 30, 2025, as key regulatory approvals remain elusive. The decision, announced in a stock exchange filing on September 30, cites ongoing processes with the National Company Law Tribunal (NCLT) Mumbai Bench and various government authorities, including the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

The revised timeline, invoked under Clause 39.7 of the scheme, allows flexibility if conditions precedent are unmet. Originally unveiled in September 2023 as a six-way split, the plan was scaled back to fiveentities after shelving the base metals demerger: Vedanta Limited (zinc, copper, and parent), Vedanta Aluminium Metal Ltd, Vedanta Oil & Gas Ltd, Vedanta Steel & Ferrous Materials Ltd, and Talwandi Sabo Power Ltd (TSPL). Shareholders will receive one share each in the resulting companies for every Vedanta share held, aiming to sharpen focus and attract sector-specific investments.

Recent hurdles included government objections over alleged non-disclosures, leading to an NCLT hearing deferral to October 8, and a settlement with Chinese creditor SEPCO Electric Power for TSPL's ₹1,251 crore debt. Despite these, February meetings saw 99.99% shareholder approval and strong creditor backing.

Vedanta's Chairman emphasized the restructuring's role in "unlocking shareholder value," projecting EBITDAgrowth of 16-20% across units by FY27.

Analysts view the extension positively, noting it mitigates risks while preserving scheme integrity if one part fails, others proceed. Shares dipped 1.2% to ₹465 on the news, reflecting cautious optimism amid a volatile metals market. As India bolsters its critical minerals push, Vedanta's pivot could redefine its global footprint, but swift clearances are crucial for Q1 FY26 execution.

भारतीय रेलवे वैश्विक निर्यातक के रूप में उभर रहा: 16 से अधिक देशों को उपकरण निर्यात, मंत्रालय

'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' की छाप, मार्होरा प्लांट से गिनी को 150 इंजन का ऑर्डर

चेन्नई: भारत की प्रमुख कमर्शियल वाहन कंपनी अशोक लीलैंड ने सितंबर 2025 में कुल बिक्री में 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने 18,813 वाहन बेचे, जो पिछले साल के सितंबर में 17,233 यूनिट से अधिक है। घरेलू बाजार में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 17,209 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि निर्यात में उल्लेखनीय सुधार देखा गया।

मध्यम एवं भारी कमर्शियल वाहन (एमएंडएचसीवी) सेगमेंट में ट्रक और बसों की संयुक्त बिक्री 11,808 यूनिट रही, जो 7 प्रतिशत ऊपर है। हालांकि, इस सेगमेंट में ग्रोथ मॉडरेट रही, लेकिन लाइट कमर्शियल वाहन (एलसीवी) ने बाजी मारी। एलसीवी बिक्री 15 प्रतिशत चढ़कर 6,701 यूनिट हो गई, जो छोटे एवं मध्यम व्यवसायों की बढ़ती मांग को दर्शाती है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ धीरज पांडेय ने कहा, "यह वृद्धि हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो की मजबूती और ग्राहक विश्वास का प्रमाण है। त्योहारी सीजन की शुरुआत में मांग में तेजी आई है।" विशेषज्ञों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की रिकवरी ने सेक्टर को बल दिया। हालांकि, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियां बनी हुई हैं।

अगस्त 2025 की तुलना में सितंबर में 23 प्रतिशत की मासिक वृद्धि ने कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अशोक लीलैंड 1.8 लाख यूनिट का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह प्रदर्शन हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी को ऑटो सेक्टर में अग्रणी बनाए रखेगा। निवेशक अब अक्टूबर के आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं, जो त्योहारों की असर दिखाएंगे।

PPFAS म्यूचुअल फंड ने CFO हिमांशू बोहरा के इस्तीफे की घोषणा की

29 सितंबर से प्रभावी, फ्लेक्सी कैप फंड में आईडीसीडब्ल्यू विकल्प जोड़ने के साथ बदलाव

मुंबई: भारत के प्रमुख वैल्यू इन्वेस्टिंग आधारित म्यूचुअल फंड हाउस PPFAS म्यूचुअल फंड ने अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) और होल-टाइम डायरेक्टर हिमांशू बोहरा के इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा की है। कंपनी के नोटिस कम एडेंडम के अनुसार, बोहरा ने PPFAS एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (PPFAS AMC) के बोर्ड से 29 सितंबर 2025 को व्यवसाय के अंतिम घंटों के बाद इस्तीफा दे दिया। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन (एसएआई) से बोहरा का नाम हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो एसएआई का अभिन्न हिस्सा बनेगी।

PPFAS, जो लंबी अवधि के वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है, ने कहा कि यह बदलाव कंपनी की अन्य योजनाओं या शर्तों को प्रभावित नहीं करेगा। बोहरा की भूमिका वित्तीय प्रबंधन और अनुपालन में महत्वपूर्ण रही, लेकिन इस्तीफे का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। कंपनी ने नए सीएफओ की नियुक्ति पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन एसईबीआई नियमों के तहत जल्द खुलासा करने की उम्मीद है।

इसी बीच, फंड हाउस ने अपनी फ्लैगशिप स्कीम पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड में फंडामेंटल में बदलाव की घोषणा की। अब यह स्कीम डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के अलावा ग्रोथ के साथ-साथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉल (आईडीसीडब्ल्यू) विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। एसईबीआई नियमों के अनुपालन में, निवेशकों को बदलाव से असहमति जताने के लिए 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक 30 दिनों का एग्जिट विंडो दिया गया है, जिसमें रिडेम्पशन या स्विच पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। यह विकल्प नियमित आय चाहने वाले निवेशकों के लिए लचीलापन लाएगा।

PPFAS का फ्लेक्सी कैप फंड देश का सबसे बड़ा एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड है, जिसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हैं। यह बदलाव बाजार की अस्थिरता में निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीएफओ बदलाव से फंड हाउस की स्थिरता पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन मजबूत फंडामेंटल्स इसे झेल लेगा। निवेशक अब एयूएम ग्रोथ और नए अपॉइंटमेंट पर नजर रखे हुए हैं।

Coal India Grapples with Monsoon Woes: September Output Dips 3.9% to 48.97 MT

H1 FY26 Production Slips to 329 MT Amid Waterlogging; 875 MT Annual Target Under Pressure

New Delhi: State-run Coal India Limited (CIL), the world's largest coal miner, reported a 3.9% decline in September production to 48.97 million tonnes (MT), down from 50.94 MT in the same month last year, primarily due to heavy monsoon rains and waterlogging in key mining regions. The company, which supplies over 80% of India's domestic coal, highlighted disruptions in subsidiaries like Bharat Coking Coal Ltd (BCCL), Central Coalfields Ltd (CCL), Western Coalfields Ltd (WCL), and Mahanadi Coalfields Ltd (MCL).

The April-September (H1 FY26) output further slid to 329.14 MT from 341.35 MT in the previous fiscal half, underscoring seasonal vulnerabilities despite government initiatives to ramp up mining for energy security. Offtake, however, held relatively steady at 53.56 MT, a marginal 1.1% drop from 54.16 MT year-on-year, buoyed by steady power sector demand.

CIL remains committed to its ambitious FY26 targets of 875 MT production and 900 MT dispatch, aiming to curb coal imports amid surging electricity needs. "Monsoon impacts are temporary; we're accelerating auctioned mine ramp-ups and technology adoption for efficiency," a company spokesperson stated. Yet, analysts warn that prolonged weather disruptions could inflate power tariffs and strain the grid, especially with India's coal-fired plants generating 70% of electricity.

This dip contrasts with FY25's record 1.04 billion tonnes national output, driven by captive mining growth. As the country eyes 1.2 billion tonnes by FY30 to fuel industrialization, CIL's pivot to sustainable practices like mine closure and reclamation adds complexity. Investors shrugged off the news, with shares inching up 0.5% to ₹485, betting on festive season demand. With winter looming, all eyes are on Q3 recovery to realign with self-reliance goals.

India Rolls Out Solar Import Tracker to Safeguard Domestic Boom

MNRE's New System to Scrutinize Origin and Compliance, Aiming for Self-Reliance Amid Rising Capacities

New Delhi: In a strategic push towards energy independence, India is gearing up to launch a dedicated Import Monitoring System (IMS) for solar equipment, enabling real-time tracking of imports' origin, content, and compliance with harmonised system codes. The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has forwarded the proposal to the Ministry of Commerce, with implementation expected within days, as revealed by Secretary Bhupinder Singh Bhalla.

This initiative, modeled after monitoring frameworks for steel and paper imports, will mandate online pre-shipment registrations and automatic clearances, curbing unchecked inflows primarily from China, which dominates over 80% of global solar supply chains. "The system will enhance transparency and protect nascent domestic manufacturing," Bhalla told reporters,

emphasizing its synergy with the Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) policy. From June 2026, a comprehensive list for solar cells will enforce local sourcing in government projects like PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and PM-KUSUM.

India's solar module capacity has surged past 100 GW, with cells at 27 GW, projected to hit 200 GW and 100 GW by FY28 outpacing the 50 GW annual demand. Exports reached $1.03 billion in FY23, underscoring self-sufficiency gains. Yet, challenges persist: anti-dumping probes into Chinese encapsulants and a Rs 3,500 crore incentive for critical minerals aim to slash import reliance further.

Experts hail the IMS as a "game-changer" for fair competition, potentially reducing project costs long-term by fostering local innovation. As India targets 500 GW renewables by 2030, this tracker could redefine the sector's global footprint, balancing growth with protectionism.

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	losing Rat	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	24894	25318	25111	25003	24796	24688	24481	24373
BANK NIFTY	55589	57446	56531	56060	55145	54674	53759	53288
SENSEX	81207	82661	81956	81582	80877	80503	79798	79424
FINNIFTY	26427	27162	26800	26613	26251	26064	25702	25515
MIDCAP	12794	13178	12992	12893	12707	12608	12422	12323
ACC	1847	1916	1884	1866	1834	1816	1784	1766
AXISBANK	1185	1269	1228	1207	1166	1145	1104	1083
ABCAPITAL	305	338	322	313	297	288	272	263
BHARTIARTL	1894	2012	1970	1932	1890	1852	1810	1772
BHEL	245	265	256	250	241	235	226	220
BIOCON	352	374	363	358	347	342	331	326
CDSL	1490	1562	1531	1511	1480	1460	1429	1409
DATAPATTERN	2830	3333	3103	2966	2736	2599	2369	2232
ESCORTS	3580	3873	3785	3682	3594	3491	3403	3300
EICHERMOTOR	6935	7260	7161	7048	6949	6836	6737	6624
FEDERAL BANK	192	203	199	196	192	189	185	182
GRINFRAPOJECT	1243	1312	1283	1263	1234	1214	1185	1165
HDFCBANK	964	1007	989	976	958	945	927	914
HCLTECH	1392	1430	1417	1405	1392	1380	1367	1355
HINDUNILVR	2539	2682	2615	2577	2510	2472	2405	2367
HAL	4871	5104	4990	4931	4817	4758	4644	4585
HYUNDAI	2509	2852	2779	2644	2571	2436	2363	2228
IOC	151	161	156	154	149	147	142	140
ICICIBANK	1365	1419	1399	1382	1362	1345	1325	1308
INFY	1447	1504	1484	1466	1446	1428	1408	1390
ITC	405	417	412	409	404	401	396	393
KOTAKBNK	2108	2292	2200	2154	2062	2016	1924	1878
LICHOUSING	580	608	595	588	575	568	555	548
LT	3743	3917	3831	3787	3701	3657	3571	3527
LUPIN	1975	2124	2065	2020	1961	1916	1857	1812
MARUTI	15810	16785	16561	16186	15962	15587	15363	14988
M&M	3460	3613	3557	3508	3452	3403	3347	3298
MGL	1288	1390	1349	1319	1278	1248	1207	1177
MAZGAONDOC	2884	3125	3007	2946	2828	2767	2649	2588
PFC	413	453	440	426	413	399	386	372
RECLTD	381	413	402	391	380	369	358	347
RELIANCE	1363	1413	1400	1382	1369	1351	1338	1320
SBIN	867	900	889	878	867	856	845	834
SUNPHARMA	1630	1725	1687	1658	1620	1591	1553	1524
SHRIRAMFINANCE	648	711	681	664	634	617	587	570
TITAN	3450	3654	3564	3507	3417	3360	3270	3213
TCS	2903	2994	2962	2932	2900	2870	2838	2808
TATAMOTORS	716	820	779	748	707	676	635	604
UPL	676	727	703	690	666	653	629	616
VALIENT	342	375	360	351	336	327	312	303
WIPRO	241	251	248	244	241	237	234	230

आंध्र प्रदेश की ट्रांसमिशन फीस माफी मांग ने अदानी सोलर डील को नई चुनौती दे दी है।

अमेरिकी रिश्वत जांच के बीच 7,000 MW समझौते पर विवाद, राज्य की मांग से लागत 40% बढ़ने का खतरा

नई दिल्ली: अमेरिकी रिश्वत जांच के घेरे में चल रही अदानी ग्रीन एनर्जी की सोलर पावर डील को अब आंध्र प्रदेश की ट्रांसमिशन फीस माफी की मांग ने नई चुनौती दे दी है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया (SECI) के माध्यम से 2021 में हस्ताक्षरित 7,000 मेगावाट सोलर पावर समझौते के तहत ट्रांसमिशन शुल्क माफ करने की गारंटी की मांग की है। केंद्र सरकार के कानून के तहत यह शुल्क अनिवार्य है, जो सोलर बिजली की लागत को लगभग 40 प्रतिशत बढ़ा सकता है।

अप्रैल से अदानी ने कई पत्र भेजकर राज्य को पावर ऑफटेकिंग शुरू करने का आग्रह किया है। नवीनतम पत्र में कंपनी ने 4,312 MW सोलर पावर सप्लाई के लिए तैयार होने की बात कही। यह डील आंध्र प्रदेश, अदानी ग्रीन और SECI के बीच हुई थी, जहां SECI अनुबंधों का पालन सुनिश्चित करने वाली मध्यस्थ संस्था है। राज्य के अधिकारियों की सलाह के विरुद्ध यह सौदा मंजूर किया गया था, जो अब विवादास्पद हो गया है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और अन्य पर 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देकर आंध्र में पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का आरोप लगाया है। भारत में विपक्षी दल जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन नियामक अभी चुप हैं। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की नई TDP सरकार PSA की समीक्षा कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि फीस माफी संभव नहीं, क्योंकि SECI को ऐसा कोई अधिकार नहीं। इससे डील रद्द होने या अदानी को नुकसान का डर है।

यह विवाद भारत के 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। अदानी समूह ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन निवेशक चिंतित हैं। राज्य को सस्ती बिजली की जरूरत है, लेकिन कानूनी बाधाएं समझौते को लटका रही हैं। आने वाले दिनों में SECI की भूमिका और केंद्र के हस्तक्षेप पर नजरें टिकी हैं।

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in